भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4018
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी

4018. एडवोकेट चंद्र शेखर:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में खराब मोबाइल नेटवर्क कवरेज, बार-बार कॉल ड्रॉप होने और अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे छात्रों, किसानों, व्यवसायियों और आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो ततसंबंधी व्यौरा क्या है,
(ख) उत्तर प्रदेश में खराब मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का दूरसंचार सेवाप्रदाता-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार का 'न्यूनतम सेवा गुणवत्ता मानक' को लागू करने, बार-बार सेवा में व्यवधान के लिए जवाबदेही की स्पष्टता से तय करने और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण उपाय प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए मोबाइल टावरों और पूर्ण की गई दूरसंचार अवसंरचना परियोजनाओं तथा भविष्य की विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) गुणवत्ता सेवा (क्यूओएस) विनियम में निर्धारित विभिन्न क्यूओएस मापदंडों के बेंचमार्कों के आधार पर सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है। जून-26 के माह के लिए ट्राई द्वारा प्रकाशित प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट के

अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित देश में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) नेटवर्क से संबंधित मानकों के लिए सभी क्यूओएस बेंचमार्क को पूरा कर रहे हैं।

(ख): परिवाद/शिकायतों की जिला वार रिपोर्ट का केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल पर व्यवस्था नहीं है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी)-वार शिकायतों का ब्योरा निम्नानुसार है:

उत्तर प्रदेश राज्य के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में प्राप्त शिकायतों का वित्तीय वर्ष वार टीएसपी -वार ब्योरा						
वित्तीय वर्ष	**बीएसएनएल**	**एमटीएनएल**	**एयरटेल**	**आरजेआईएल**	**वीआईएल**	**कुल**
2023-24	575	15	771	1131	232	**2724**
2024-25	1147	31	981	1268	245	**3672**
2025-26	1260	17	1671	3228	419	**6595**

इन सभी शिकायतों का संबंधित टीएसपी /डीओटी इकाइयों द्वारा पोर्टल पर निपटारा कर दिया गया है।

(ग): टीएसपी द्वारा बेहतर गुणवत्ता की सेवा सुनिश्चित करने के लिए, ट्राई ने दिनांक 02.08.2024 को संशोधित क्यूओएस विनियमों अर्थात् "द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ एक्सेस (वायरलाइन्स एंड वायरलेस) एंड ब्रॉडबैंड (वायरलाइन एंड वायरलेस) सर्विस रेगुलेशंस, 2024 (06 ऑफ 2024)' के तहत क्यूओएस मापदंडों के लिए अधिक कठोर मानदंड निर्धारित किए हैं। जहां भी मानदंड पूरा नहीं किए जाते हैं, वहां संबंधित सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और सेवा प्रदाता के प्रत्युत्तर पर विचार करने के बाद, सेवा प्रदाता पर क्यूओएस मापदंडों के अनुपालन न किए जाने के लिए फाइनेंसियल डिसइनसेन्टिव लगाया जाता है।

(घ): वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 411249 बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) कार्यशील हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में संस्थापित बीटीएस का वित्तीय वर्षवार ब्योरा निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष के अनुसार संस्थापित बीटीएस की संख्या**			
	2023-24	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 (चालू वर्ष)**
उत्तर प्रदेश	51930	5116	25347	6492

दूरसंचार विभाग ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित देश भर के चिह्नित किए गए सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं को निष्पादित किया है। पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में विभिन्न डीबीएन योजनाओं के तहत कुल 236 टावर संस्थापित किए गए हैं। ब्योरा नीचे दिया गया है:

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में संस्थापित टावरों की संख्या		
वित्तीय वर्ष 2023-24	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
4	138	94

******